



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर, 3, 2013/आश्विन 11, 1935

No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2013/ASVINA 11, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 03 अक्टूबर, 2013

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 तथा 28 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/26/6667. - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 29क के अधीन जारी भारत सरकार की तारीख 30 जुलाई 1992 की अधिसूचना संख्या का.आ. 573(अ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) तथा धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा तारीख 1 मार्च 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.184(अ) को विखंडित करता है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, और यह घोषित करता है कि जिस राज्यक्षेत्र तक उक्त अधिनियम का विस्तार होता हो उस राज्यक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, बोर्ड की अनुज्ञा के बिना, प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के लिए कोई संविदा, जो किसी ऐसी संविदा से भिन्न हो जो निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक के अधीन आती हो, नहीं करेगा, अर्थात्, -

- (क) हाजिर संविदा (स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट) ;
- (ख) प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के लिए संविदाएँ अथवा व्युत्पन्नियों में संविदाएँ, जो उक्त अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और ऐसे अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों तथा उप-विधियों के अधीन अनुज्ञेय हैं ;
- (ग) अग्रक्रय के लिए संविदाएँ जिनमें कंपनियों या अन्य निगमित निकाय के शेयरधारक करारों या संगम-अनुच्छेद में अंतर्विष्ट प्रथम इंकार का अधिकार, अथवा टैग-अलॉग या ड्रैग-अलॉग के अधिकार सम्मिलित हैं ;
- (घ) कंपनियों या अन्य निगमित निकाय के शेयरधारक करारों या संगम अनुच्छेद में संविदाएँ, प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करने हेतु उनके अंतर्गत अंतर्विष्ट विकल्प का प्रयोग किये जाने के अनुसरण में प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के लिए, जहाँ -
- (i) अंडरलाइंग प्रतिभूतियों का हक और स्वामित्व ऐसी संविदा के विक्रय पक्षकार (सैलिंग पार्टी) द्वारा संविदा किये जाने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तक लगातार धारित हो ;
 - (ii) उनके अंतर्गत अंतर्विष्ट किसी विकल्प के प्रयोग के अनुसरण में अंडरलाइंग प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के लिए संदेय कीमत या प्रतिफल, तत्समय प्रवृत्त यथा लागू समस्त विधियों के अनुपालन में हो ; और
 - (iii) संविदा का निपटान अंडरलाइंग प्रतिभूतियों के वास्तविक परिदान (डिलीवरी) के तौर पर हुआ हो :

परंतु यह कि उपरोक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संविदाएँ, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार होंगी:

परंतु यह और कि इस अधिसूचना में दी हुई कोई भी बात किसी संविदा, जो इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व की गयी हो, को प्रभावित या विधिमान्य नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण .- यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त खंड (ग) तथा (घ) में उल्लिखित संविदाएँ, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 18क में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, विधिमान्य होंगी :

परंतु यह भी कि सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण संबद्ध प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के लिए कोई संविदा, मुद्रा व्युत्पन्नियों (करेंसी डेरिवेटिव), ब्याज दर व्युत्पन्नियों में संविदाएँ और ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में की गयी तुरंत-अग्रिम संविदाएँ (रैडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट), -

- (क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों

या उप-विधियों अथवा उक्त अधिनियमों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेशों ;

- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों या जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों ;
- (ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार की जायेंगी ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन [III/4/असाधारण/69जैडबी/13](#)]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd October, 2013

Notification under Section 16 and 28 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956

LAD-NRO/GN/2013-14/26/6667.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 28 and sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), read with Government of India notification number S.O. 573(E), dated the 30th July, 1992 issued under Section 29A of the said Act, the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as ‘the Board’) hereby rescinds the notification number S.O.184(E), dated the 1st March, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, and declares that no person in the territory to which the said Act extends, shall, save with the permission of the Board, enter into any contract for sale or purchase of securities other than a contract falling under any one or more of the following, namely:—

(a) spot delivery contract;

(b) contracts for sale or purchase of securities or contracts in derivatives, as are permissible under the said Act or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the rules and regulations made under such Acts and rules, regulations and bye-laws of a recognised stock exchange;

(c) contracts for pre-emption including right of first refusal, or tag-along or drag-along rights contained in shareholders agreements or articles of association of companies or other body corporate;

(d) contracts in shareholders agreements or articles of association of companies or other body corporate, for purchase or sale of securities pursuant to exercise of an option contained therein to buy or sell the securities, where-

(i) the title and ownership of the underlying securities is held continuously by the selling party to such contract for a minimum period of one year from the date of entering into the contract;

(ii) the price or consideration payable for the sale or purchase of the underlying securities pursuant to exercise of any option contained therein, is in compliance with all the laws for the time being in force as applicable; and

(iii) the contract is settled by way of actual delivery of the underlying securities:

Provided that the contracts specified in clauses (a) to (d) above, shall be in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules or regulations made thereunder:

Provided further that nothing contained in this notification shall affect or validate any contract which has been entered into prior to the date of this notification.

Explanation.- It is hereby clarified that the contracts mentioned in clauses (c) and (d) above shall be valid notwithstanding anything contained in Section 18 A read with clause (d) of sub-section (1) of section 23 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956):

Provided also that any contract for sale or purchase of government securities, gold related securities, money market securities, contracts in currency derivatives, interest rate derivatives and ready forward contracts in debt securities entered into on the recognised stock exchange shall be entered into in accordance with,

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

(b) the rules made or guidelines or directions issued, under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), by the Reserve Bank of India;

(c) the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

U. K. SINHA, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./69ZB/13]